

पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

प्रलम्बिस लयि:

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA), जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जनजातियों के लयि विकास कार्य योजना (DAPST), पोषण अभियान, वन अधिकार अधनियम, 2006 (FRA), टीकाकरण, सवदेश दरशन योजना, सकिल सेल रोग, प्रधानमंत्री आदि आदरश ग्राम योजना

मेन्स के लयि:

जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु सरकारी नीतयिँ और हसतकषेप ।

स्रोत: पीआईबी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रमिडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजकि-आर्थकि स्थति में सुधार के लयि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) को मंजूरी दी ।

PMJUGA के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परचिय:** यह जनजातीय बहुल गाँवों और आकांकषी ज़िलों में जनजातीय परवारों के कल्याण के लयि एक केंद्र परायोजति योजना है ।
- **लकषति कषेत्र और कवरेज:** यह 30 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के सभी आदवासी बाहुल्य गाँवों के 549 ज़िलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करेगा ।
 - इससे लगभग 63,000 गाँव और 5 करोड से अधिक जनजातीय लोग लाभानवति होंगे ।
 - **वर्ष 2011 की जनगणना** के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजात (एसटी) की आबादी 10.42 करोड (8.6%) है, जसिमें 705 से अधिक जनजातीय समुदाय शामिल हैं ।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत सरकार की वभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनके बीच स्वास्थ्य, शकिषा, आजीवकि जैसे सामाजकि बुनयादी ढाँचे के संदरभ में अंतराल को कम करना है ।
- **मशिन के लकष्य:** इसमें 25 हसतकषेप शामिल हैं, जनिहें अनुसूचित जनजातियों के लयि विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत आवंटति धनराशिके माध्यम से 17 मंत्रालयों द्वारा अगले 5 वर्षों में कार्यानवति कयि जाएगा ताकनिमिनलखिति लकष्यों को प्राप्त कयि जा सके ।
 - **सकषम बुनयादी ढाँचे का विकास:**
 - पात्र परवारों के लयि पक्का आवास: पात्र एसटी परवारों को **PMAY (ग्रामीण)** के तहत पक्का आवास मलिगा, जसिमें नल का जल (**जल जीवन मशिन**) और वदियुत की आपूरत शामिल है । पात्र एसटी परवारों को **आयुषमान भारत कारड (PMJAY)** का भी लाभ मलिगा ।
 - गाँव के बुनयादी ढाँचे में सुधार: अनुसूचित जनजात बाहुल्य गाँवों में सभी मौसम के लयि सडक संपर्क सुनशिचति करना (**PMGSY**), मोबाइल कनेक्टविटी (**भारत नेट**) और इंटरनेट तक पहुँच परदान करना, स्वास्थ्य, पोषण और शकिषा में सुधार के लयि बुनयादी ढाँचे (**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन, समग्र शकिषा और पोषण अभियान**) को बढावा देना ।
 - **आर्थकि सशकतीकरण को बढावा:** यह प्रशकिषण (**कौशल भारत मशिन**) तक पहुँच परदान करके, जनजातीय बहुउद्देशीय वपिणन केंद्र (TMMC) से वपिणन सहायता के साथ **वन अधिकार अधनियम, 2006 (FRA)** पढटा धारकों के लयि कृषा, पशुपालन और मत्स्य पालन कषेत्रों में सहायता के माध्यम से कौशल विकास, उदयमति संवर्दधन और उन्नत आजीवकि (स्वरोजगार) पर केंदरति है ।
 - **गुणवत्तापूरण शकिषा तक पहुँच का सार्वभौमकिरण:** स्कूल और उच्च शकिषा में **सकल नामांकन अनुपात (GER)** को बढाने और ज़िला/ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में आदवासी छात्रावासों की स्थापना करके अनुसूचित जनजात के छात्रों के लयि गुणवत्तापूरण शकिषा को ससती और सुलभ बनाने के परयास कयि जाएंगे (समग्र शकिषा अभियान) ।
 - **सवस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था:** इसका उद्देश्य उन कषेत्रों में **मोबाइल मेडकिल इकाइयों** के माध्यम से **IMR, MMR** और **टीकाकरण** कवरेज के राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचना है, जो उप केंद्र मैदानी कषेत्रों में 10 कलिमीटर से अधिक और पहाडी कषेत्रों में 5 कलिमीटर से अधिक दूर हैं ।
- **मानचतिरण और नगिरानी:** इस मशिन के अंतरगत शामिल जनजातीय गाँवों को **पीएम गति शक्ति पोर्टल** पर अंकति कयि जाएगा, जसिमें संबधति मंत्रालय द्वारा योजना वशिषिट आवश्यकताओं के लयि पहचाने गए अंतरालों को शामिल करने के साथ सर्वशरेष्ट प्रदरशन करने वाले ज़िलों को

पुरस्कृत कथिा जाएगा ।

नोट:

- DAPST भारत में जनजातीय विकास के लिये एक रणनीति है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय और 41 अन्य मंत्रालय एवं वभिाग DAPST के तहत जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये धन आवंटति करते हैं ।
 - इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सचिाई, सडक, आवास, वदियुतीकरण और रोजगार शामिल हैं ।

PMJUGA के तहत आदवासियों के बीच आजीवकिा को बढावा देने हेतु अभनिव योजनाएँ क्य़ा हैं?

- जनजातीय गृह प्रवास: जनजातीय कषेत्रों में पर्यटन को बढावा देने और वैकल्पकि आजीवकिा प्रदान करने के लिये, पर्यटन मंत्रालय द्वाारा [सुवदेश दरशन योजना](#) के तहत 1,000 गृह प्रवासों को बढावा दयिा जाएगा ।
 - पर्यटन की संभावना वाले गाँवों को 5-10 होमस्टे के लिये वत्ति पोषण मल्लिगा, जसिमें प्रत्येक परिवार को दो नए कमरे बनाने के लिये 5 लाख रुपये, मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिये 3 लाख रुपये औरग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिये 5 लाख रुपये तक का अनुदान मल्लिगा ।
- वन अधिकार धारकों के लिये सतत् आजीवकिा: इस मशिन का वशिष ध्यान वन कषेत्रों में वन अधिकार अधनियिम, 2006 के तहत 22 लाख पट्टा धारकों पर है । इसका उददेश्य वन अधिकारों की मान्यता में तेजी लाना, आदवासी समुदायों को सशकत बनाना और वभिनिन सरकारी योजनाओं के माध्यम से इन्हें सतत् आजीवकिा प्रदान करना है ।
- सरकारी आवासीय वदियालयों और छात्रावासों के बुनयिादी ढाँचे में सुधार: इस पहल में स्थानीय शैक्षकि संसाधनों को उन्नत बनाने, नामांकन को बढावा देने और इन संस्थानों में छात्रों को बनाए रखने के लिये आदवासी आवासीय वदियालयों, छात्रावासों एवं आश्रम वदियालयों के बुनयिादी ढाँचे में सुधार करना शामिल है ।
- सकिल सेल रोग के नदिान हेतु उन्नत सुवधिाएँ: एम्स और उन राज्यों के प्रमुख संस्थानों में सक्षमता केंद्र (CoC) स्थापति कयि जाएंगे जहाँ सकिल सेल रोग प्रचलति है ।
 - CoC के पास प्रसवपूर्व नदिान हेतु नवीनतम सुवधिाएँ, प्रौद्योगकिी, कार्मकि और अनुसंधान क्षमताएँ होंगी, जसिकी लागत 6 करोड रुपये/CoC होगी ।
- जनजातीय बहुउददेशीय वपिणन केंद्र (TMMCs): जनजातीय उत्पादों के प्रभावी वपिणन तथा वपिणन अवसंरचना, जागरूकता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और परविहन सुवधिाओं में सुधार के लिये 100 TMMC स्थापति कयि जाएंगे ।

//



Scheduled Tribes



STs constitute **8.6%** of the total population of India (Census 2011).



There are over 730 Scheduled Tribes **notified** under Article 342 of the Constitution of India.



Article 342 of the **Indian** Constitution outlines the procedures for specifying Scheduled Tribes (STs).



Article **275(1)** of the Constitution of India guarantees grants-in-aid from the Consolidated Fund of India each year for promoting the welfare of Scheduled Tribes.



Particularly Vulnerable Tribal Groups (**PVTGs**) are more vulnerable among the tribal groups. Among the 75 listed PVTGs, the highest number is found in Odisha.



Bhil is the largest tribal group followed by the Gonds.



Madhya Pradesh has the highest tribal population in India (Census 2011).



PMJUGA की आवश्यकता क्या है?

- **नरिधनता:** जनजातीय समुदाय अक्सर **नरिधन** होने के साथ संसाधनों तक इनकी पहुँच सीमित होती है। पूर्ववर्ती **योजना आयोग** ने अनुमान लगाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजात के व्यक्तियों का प्रतिशत 45.3% (2011-12) और शहरी क्षेत्रों में 24.1% (2011-12) था।
 - PMJUGA के तहत **रोज़गार** सृजन को बढ़ावा देने और गरीबी में कमी लाने के लिये आदिवासी ज़िलों में **कौशल केंद्र** खोले जाएंगे।
- **भूमि अधिकार और वसिस्थापन:** कई आदिवासी समुदायों को विकास परियोजनाओं, **खनन एवं वनों की कटाई के कारण वसिस्थापित होना पड़ता है**। आदिवासियों के पास अक्सर औपचारिक भूमि नहीं होती है, जिससे असुरक्षित स्वामित्व के साथ इनके शोषण को बढ़ावा मिलता है।
 - **PMJUGA** के तहत **अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के तहत उनके **भूमि अधिकारों को मान्यता देते हुए 22 लाख FRA पट्टे** जारी होंगे।
- **नमिन साक्षरता दर:** जनजातीय आबादी में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से **काफी कम है**।
 - **जनगणना 2011** के अनुसार अनुसूचित जनजातियों (ST) की साक्षरता दर **59% थी** जबकि अखिल भारतीय स्तर पर **समग्र साक्षरता दर 73% थी**।
 - कफायती शिक्षा के लिये **समग्र शिक्षा अभियान (SSA)** के तहत **1000 छात्रावासों का** निर्माण किया जाएगा।

- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे :** [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण \(NFHS-5\) 2019-21](#) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आदवासी बच्चों में [सट्टंगि, वेस्टिंग और कम वजन](#) की व्यापकता क्रमशः **40.9%, 23.2% और 39.5%** है। यह राष्ट्रीय औसत **35.5%, 19.3% और 32.1%** से काफी अधिक है।
 - जनजातीय लोगों में **सकिल सेल रोग (SCD)** का प्रकोप भी अधिक देखा जाता है।
 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन** के अंतर्गत **मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ उपलब्ध कराएगा**।
- **सांस्कृतिक क्षरण और पहचान :** कई जनजातीय समुदाय तीव्र **शहरीकरण** और **वैश्वीकरण** जैसे बाहरी दबावों के बीच अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिये संघर्ष करते हैं।
 - **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना** के तहत **सांस्कृतिक पहचान** को संरक्षित रखते हुए आदर्श गाँव बनाए जाएंगे।
- **सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी:** अपनी नरिधनता के बावजूद कई आदवासी लोग **बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड या 100 दिनी की रोजगार योजनाओं** के लिये जॉब कार्ड के बारे में काफी हद तक अनभिज्ञ हैं। नतीजतन, वे ऐसे लाभों से वंचित रह जाते हैं।
 - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जागरूकता सृजन के लिये विभिन्न **डिजिटल इंडिया पहलों** को बढ़ावा देगा।

अनुसूचति जनजातियों के लिये सरकार की अन्य पहल क्या हैं?

- [प्रधानमंत्री-जनजात आदवासी न्याय महा अभियान \(पीएम-जनमन\)](#)
- [ट्राइफेड](#)
- [जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन](#)
- [वशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास](#)
- [प्रधानमंत्री वन धन योजना](#)
- [एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय](#)

नषिकर्ष:

प्रधानमंत्री **जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA)** का उद्देश्य सतत विकास, बुनियादी ढाँचे, आजीविका और सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाकर आदवासी समुदायों का उत्थान करना है। **कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में** यह शक्ति, स्वास्थ्य सेवा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने, विकास अंतराल को कम करने तथा भारत में आदवासियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में आदवासी समुदायों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ बताइये?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा के पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलिमिस

प्रश्न: भारतीय संविधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लिये आदवासी भूमि को नजी पक्षों को हस्तांतरित करना शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- नौवी अनुसूची
- बारहवी अनुसूची

उत्तर: (b)

प्रश्न. सरकार ने अनुसूचति क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। नमिनलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013)

- स्वशासन प्रदान करना
- पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
- जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
- जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

उत्तर: (c)

?????

प्र. आप उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं जो दिखाते हैं कि भारत में जनजातियों में लगानुपात अनुसूचित जातियों के लगानुपात की तुलना में महिलाओं के लिये अधिक अनुकूल है? (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pm-janjatiya-unnat-gram-abhiyan>

